बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 33

अव्यावहारिक योजना

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि देश के सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों के खाते में प्रतिमाह 6,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। यह राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली लोकलुभावन कल्याणकारी योजनाओं की पेशकश का सबसे नया ताजा उदाहरण है। प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत तकरीबन 25 करोड़ लोग या औसतन 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित योजना पार्टी द्वारा पहले पेश की जाने वाली योजना से अलग है जिसके तहत गरीब परिवारों की आय को बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपये तक लाने की बात शामिल थी। इस टॉप-अप योजना से इतर नया प्रस्ताव यह है कि अगर किसी परिवार की आय 12,000 रुपये से कम है तो उसे साल में 72,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। व्यापक अनुमान है गरीब से गरीब परिवार भी महीने में कम से कम 6,000 रुपये कमा ही लेता है। यानी अगर सरकार की ओर से 6,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करा दी जाए तो ऐसे परिवार गरीबी के दायरे से बाहर आ जाएंगे। आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'न्याय' योजना को खारिज किया है। राजनीतिक दलीलों से इतर भी 'न्याय' एक बेहद खराब नीतिगत उपाय है।

मिसाल के तौर पर सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों के चयन की बात ही गलत है। विश्व बैंक ने गरीबी का नया मानक 3.20 डॉलर प्रतिदिन (क्रय शक्ति समता के आधार पर) तय किया है। 12,000 रुपये का आंकड़ा यहीं से आया है। परंतु वर्ष 2011 में हमारे अपने अनुमान के मुताबिक आबादी का 21.9 फीसदी हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था। यानी आज यह आंकड़ा तकरीबन 15 फीसदी होगा। यह संकेत दिया जा चुका है कि यह भुगतान कुछ मौजूदा योजनाओं को प्रतिस्थापित करके दिया जाएगा। लेकिन यह योजना कतई अच्छी नहीं है क्योंकि इससे मतभेद पैदा होगा और इसका विरोध भी होगा। विरोध इसलिए क्योंकि लाभार्थी पूरी तरह विभिन्न योजनाओं का अतिव्यापन नहीं करेंगे और इसलिए कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। योजना के लिए कृत्रिम ढंग से कट ऑफ सीमा का निर्धारण करना समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि इसके दायरे में आने वालों में भेद करने की गुंजाइश बहुत कम है और कई ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग भी होंगे जो इसके दायरे महज कुछ ऊपर हों। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 11,000 रुपये कमाता है तो उसे 6,000 रुपये मिलेंगे लेकिन अगर कोई 12,000 रुपये कमाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में बाहर रह जाने वालों के नाराज होने की पूरी गुंजाइश है। लाभार्थियों की पहचान करना भी समस्या होगा क्योंकि इसका कोई खामी रहित तरीका नहीं है।

परिवार के आकार में भी अंतर हो सकता है और शहरी और ग्रामीण परिवार दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है जबकि इन परिवारों के जीवन स्तर और खर्च में काफी अंतर होता है। सबसे बड़ा सवाल राजकोषीय व्यवहार्यता का है। कांग्रेस का दावा है कि इस योजना पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.2 फीसदी व्यय होगा। परंतु यह आकलन अति आशावादी है। मौजूदा जीडीपी दर के आधार पर यह उसका तकरीबन 2 फीसदी होगा। आर्थिक वृद्धि के साथ तीन वर्ष पश्चात यह विस्तारित जीडीपी का 1.5 फीसदी होगा। परंतु 1.2 फीसदी के अतिरिक्त व्यय पर भी न्याय राजकोष पर भारी पड़ेगा। ऐसे तमाम प्रस्ताव एकीकृत मूलभूत आय (यूबीआई) के विचार से उपजे हैं। यह विचार भी अव्यावहारिक है। अर्थशास्त्री चाहे जो भी कहें लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी सरकार मौजूदा लाभ समाप्त नहीं कर सकती। लागत कम रखने के लिए चयन प्रक्रिया के साथ यूबीआई में विसंगति आती है लेकिन इससे चिह्नित करने की ऐसी समस्या खड़ी होती है जिसका हल आसान नहीं है। इसका असर क्रियान्वयन पर भी पड़ता है।

बिनय सिन्हा

नई वित्तीय व्यवस्था बना रहा है चीन

चीन अपने वित्तीय बाजारों को चरणबद्ध तरीके से खोल रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के लिए मुनाफे के अनेक अवसर तैयार हुए हैं। विस्तार से बता रहे हैं **श्याम सरन**

चीन अपनी मुद्रा रेनमिनबी (आरएमबी) के पूर्ण अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन वह अपने वित्तीय बाजार को उदार नहीं बनाना चाहता क्योंकि उसके साथ विनिमय दर की अस्थिरता और पूंजी के संभावित बहिर्गमन जैसी बातें जुड़ी हुई हैं। अब तक उसके प्रयास व्यापार समझौतों, निवेश उत्पादों और आरक्षित मुद्रा के रूप में आरएमबी का प्रयोग करके उसके अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल को मजबूत करने के रहे हैं। बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई) भी चीन को यह अवसर देती है कि वह साझेदार देशों की परियोजनाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में आरएमबी का प्रयोग करे।

इस संबंध में बड़ी पहल मार्च 2018 में की गई जब पेट्रो-डॉलर के समक्ष पेट्रो-युआन के बाजार को मजबूत करने के लिए शांघाई इंटरनैशनल एनर्जी एक्सचेंज की स्थापना की गई। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। वह तेल के सौदों का निपटान अपनी मुद्रा में करने को बढ़ावा दे रहा है। शांघाई एक्सचेंज तेल वायदा कारोबार में न्यूयॉर्क और लंदन का मुकाबला करता है और एशिया के लिए मानक दरें तय करने में सक्षम है। एक वर्ष के कारोबार में वह वायदा बाजार के 6 फीसदी हिस्से में कारोबार कर रहा है। वायदा बाजार का 15 फीसदी हिस्सा विदेशी कारोबारियों के पास है। पेट्रो-युआन बाजार को अमेरिका द्वारा रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगने का भी फायदा मिला। जैसे-जैसे इस एक्सचेंज के कामकाज में परिपक्वता आएगी, वह तेल कीमतों के लिए वेस्ट टैक्सस इंटरनैशनल और ब्रेंट का विकल्प बनेगा।

सन 2018 की एक अन्य अहम घटना है चीन के बॉन्ड बाजार में विदेशी पहुंच को अनुमति। फिलहाल इस बाजार का आकार 12.7 लाख करोड़ डॉलर का है और अगले चार वर्ष में यह दोगुना हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के बाद यह दुनिया का तीसरा बड़ा बॉन्ड बाजार है। सन 2017 में चीन ने बॉन्ड कनेक्ट की स्थापना की जो विदेशी बैंकों, सॉवरिन वेल्थ फंड और केंद्रीय बैंकों को हॉन्गकॉन्ग में प्राधिकृत संस्थानों के माध्यम से चीनी बॉन्ड में निवेश की इजाजत देता है। बहरहाल, चीनी बॉन्ड की विदेशी होल्डिंग अभी केवल 2 फीसदी है लेकिन इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। नवंबर 2018 में चीन ने घोषणा की कि बॉन्ड बाजार में अगले तीन वर्ष तक विदेशी निवेश को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और मूल्यवर्धित कर से राहत दी जाएगी। बॉन्ड कनेक्ट का इस्तेमाल करने वाले विदेशी निवेशकों का कोटा इस वर्ष 30,000 करोड़ डॉलर तक बढ़ा दिया गया है। ध्यान रहे कि चीन के घरेलू निवेशकों को विदेशी बॉन्ड में निवेश की इजाजत नहीं है। यह बात उसे सही मायनों में अंतरराष्ट्रीय और खुला बॉन्ड बाजार बनने से रोकती है।

गत वर्ष चीन की एक उपलब्धि यह भी रही कि शांघाई शेयर बाजार में कारोबार करने वाले चीन के एक श्रेणी के शेयरों को एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल किया गया। अभी सूचकांक में इनकी हिस्सेदारी 0.7 फीसदी है लेकिन एमएससीआई ने घोषणा की है कि इस वर्ष नवंबर तक यह हिस्सेदारी चार गुना हो जाएगी। स्टैंडर्ड ऐंड पुअर (एसऐंडपी) और फाइनैंशियल टाइम्स सिक्युरिटी एक्सचेंज (एफटीएसई) ने भी चीन के शेयरों को अपने उभरते बाजार के बेंचमार्क में स्थान दिया है।

बॉन्ड बाजार के उदारीकरण के साथ ही चीन इन सूचकांकों पर दबाव डाल रहा है कि इनमें सरकारी बॉन्डों को शामिल किया जाए। हाल ही में ब्लूमबर्ग बार्कले एग्रीगेटर ने कहा है कि 20 माह की अवधि में वह 363 चीनी प्रतिभूतियों को मानक सूचकांक में शामिल करेगा। इनकी हिस्सेदारी 6 फीसदी होगी। अन्य सूचकांक मसलन जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स और सिटी वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स भी इसका अनुकरण करेंगे। इन अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में चीन के शेयर और बॉन्ड को शामिल किए जाने से फंड स्वत: चीनी वित्तीय बाजारों में आएगा। अनुमान है कि पहले वर्ष में 8,000 करोड़ डॉलर की आवक चीनी शेयर बाजार में हो सकती है। चीनी बॉन्ड की खरीद 25,000 से 30,000 करोड़ डॉलर तक की हो सकती है। इसका परिणाम भारत जैसे देशों को होने वाले वित्तीय प्रवाह के अवरुद्ध होने के रूप में नजर आ सकता है।

चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरएमबी के इस्तेमाल को लेकर जो प्रयास कर रहा है, उसे देखते हुए यह भी ध्यान रखना होगा यूनियन पे दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी बन चुकी है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और वह 700 करोड़ कार्ड जारी कर चुकी है। दुनिया के 56 फीसदी बाजार पर उसका कब्जा है। इसका उपयोग प्रमुख तौर पर बाहर जाने वाले चीनी पर्यटक करते हैं लेकिन फिलहाल चीन के बाहर भी इसके 10 करोड़ उपभोक्ता हैं। कार्ड का प्रयोग दुनिया के 150 देशों में किया जा सकता है। बीआरई के साझेदार देशों में इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए बाकायदा नीति बनी है। चीन के बैंकों को विदेशों में अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिलहाल उनके पास 2 लाख करोड़ डॉलर मूल्य की विदेशी परिसंपत्ति है। बैंक ऑफ चाइना को 10 शीर्ष अंतरराष्ट्रीय बैंकों में छठा स्थान प्राप्त है।

चीन 12 वित्तीय मुक्त व्यापार क्षेत्र विकसित कर रहा है ताकि वित्तीय क्षेत्र सुधारों और उदारीकरण के साथ प्रयोग किया जा सके। इसमें शांघाई का अहम स्थान है। हालांकि इन पहलों का सकारात्मक प्रतिफल सामने नहीं आया है। इन क्षेत्रों में पूरा ध्यान वित्तीय क्षेत्र के बजाय व्यापक आर्थिक सुधार के एजेंडे की ओर स्थानांतरित हो गया है।

इन तमाम बातों और वित्तीय सुधार के एजेंडे को मिलाकर देखें तो चीन दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अपनी हैसियत का लाभ ले रहा है और अपने व्यापक बाजार तथा अंतरराष्ट्रीय कारोबारी समूहों की सहायता से आगे बढ़ रहा है। यह व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर देश को मिल रही चुनौतियों के एकदम विपरीत है। वित्तीय बाजार में चीन को जो बढ़त मिल रही है, उसे तब झटका लग सकता है जबकि अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी की शिकार हो जाए। अमेरिका और चीन के बीच के हालिया व्यापारिक विवाद के बाद ऐसा हो भी सकता है। परंतु समग्र प्रभाव में बदलाव आता नहीं दिखता। बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के लिए चीन के प्रतिभूति और बॉन्ड बाजार का खुलना मुनाफे के अप्रत्याशित अवसर लिए हुए है। चीन इस लक्ष्य को हासिल कर वैश्विक वित्तीय केंद्र बन सकता है। वैश्विक वित्तीय तंत्र में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिन्हें अभी ठीक से समझा नहीं जा रहा है।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान में सीपीआर के वरिष्ठ फेलो हैं।)

कर्मियों के नूतन विचार को 'गेमिफिकेशन' से प्रोत्साहन

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

आपके कर्मचारी क्या आसानी से भटक रहे हैं या लक्ष्यों से चूक जा रहे हैं? क्या वे एकदम तय समय पर आते और तय समय पर ही चले जाते हैं? कुछ कर्मी हमेशा इसी तरह काम करते हैं और उन पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस तरह का काम कर रहे हैं? लेकिन अगर नकारात्मक भावभंगिमा और झुके हुए कंधों वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है तो अपने बेहतरीन कर्मियों को बाहर जाने से रोकने के लिए कोई कदम उठाना ही होगा।

इसका समाधान सरल नहीं है। दुनिया की कुछ शीर्ष कंपनियां कर्मियों का प्रदर्शन सुधारने और उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं। इसके बावजूद उनके आधे से अधिक कर्मी कल्पनालोक में विचरण कर रहे हैं और दीर्घावधि करियर के बजाय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी को ही तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि कुछ कंपनियों ने कर्मियों के लिए नई व्यवस्थाएं अपनाई हैं। लोकप्रिय हो रहा ऐसा ही एक तरीका 'गेमिफिकेशन' यानी काम को खेल की शक्ल देना है। भले ही यह अवधारणा नई न हो लेकिन कई कंपनियों ने नई पीढ़ी के कर्मचारियों को लुभाने के लिए इसे अपनाया है। इन कर्मियों की शिकायत रहती है कि उन्हें अपना बेहतरीन काम दिखाने का मौका नहीं मिलता है और अपने विचारों एवं सुझावों से अवगत कराने का भी कोई तरीका नहीं होता है। गेमिफिकेशन से इस शिकायत को दूर कर कर्मियों को प्रबंधन के साथ जोड़ने में मदद मिलती है।

गूगल कंपनी ने एक यात्रा व्यय गेम शुरू किया है जिसमें कर्मचारियों से अपने कारोबारी यात्राओं से जुड़े खर्चों का हिसाब रखने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस गेम में प्रेरित करने वाला कारक यह है कि कर्मी जितनी रकम बचाएगा, वह उसे वेतन के साथ जोड़कर दे दी जाएगी। गूगल सॉफ्टवेयर तैयार करने की एक प्रतिस्पर्द्धा 'गूगल कोड जैम' भी आयोजित करता रहा है जिसके जरिये नई प्रतिभाओं की तलाश की जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपरों और इंजीनियरों को इस गेम का हिस्सा बनने के लिए 50,000 डॉलर की इनामी राशि भी आकर्षित करती है।

मानव संसाधन विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मियों के भीतर हल्की प्रतिस्पर्द्धा का अहसास जगाने से न केवल उनमें सीखने की ललक बढ़ती है बल्कि वे एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। गेमिफिकेशन इस विचार पर आधारित है कि लोग खेल खेलना पसंद करते हैं और ऐसा केवल बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्क होने पर भी जारी रहता है। फोर्ब्स के मुताबिक 80 फीसदी स्मार्टफोन धारक अपने फोन पर मोबाइल गेम खेलते हैं और करीब 50 फीसदी लोग तो रोजाना गेम खेलते हैं। इसके अलावा मोबाइल गेम ऐप का इस्तेमाल पुरुष एवं महिला दोनों समान रूप से करते हैं। हालांकि वयस्कों की तुलना में किशोर मोबाइल फोन पर अधिक गेम खेलते हैं लेकिन 62 फीसदी वयस्क भी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

सिस्को अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी दक्षता के बारे में बताती है। बहुस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल लोगों को कई तरह के पाठ्यक्रमों से गुजरते हुए सोशल मीडिया 'मास्टर' का तमगा हासिल करने की चुनौती दी जाती है। कार्यक्रम में प्रतिस्पर्द्धा का अवयव समाहित होने से इसे काफी पसंद किया गया।

गेमिफिकेशन असल में खेल-केंद्रित सोच को खेल से इतर कार्यों में भी लागू करने की एक आसान रणनीति है। यह कर्मचारियों के लिए गैर-खेल गतिविधियों को अधिक रोचक एवं मजेदार बना देता है। मार्केटिंग के चतुर खिलाड़ी उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बढ़ाने और उनके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे बड़ी सोच यही होती है कि कंपनियों को ब्रांड के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद मिलती है। किसी गेम की तरह रवैया अपनाने वाली कंपनी के लिए गेमिफिकेशन यह दर्शाता है कि ब्रांड और कंपनी की संस्कृति नवाचार एवं रचनात्मकता में यकीन करने वाली है।

डोमिनोज ने यह काम बखूबी अंजाम दिया था। उसके पिज्जा मुगल गेम में हिस्सा लेने वाले लोगों को नए स्वाद एवं टॉपिंग्स वाले पिज्जा के बारे में सुझाव देने और उस उत्पाद की बिक्री पर उन्हें एक निश्चित राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। इस गेम ने डोमिनोज के बारे में काफी ब्रांड जागरूकता पैदा की और संभावित कर्मियों के बीच यह संदेश भी दिया जा सका कि कंपनी नए विचारों को लेकर काफी खुली राय रखती है।

निस्संदेह, कर्मचारी संपर्क मानव संसाधन के बुनियादी उसूलों में से एक है और इसीलिए इस विभाग के तमाम मुखिया गेमिफिकेशन से प्रतिभा प्रबंधन एवं कंपनी संस्कृति में बदलाव लाने के तरीकों पर गौर करते रहे हैं। गेम में मिलने वाले अंक, दूसरे कर्मियों के साथ स्पर्द्धा और खेल के नियमों का इस्तेमाल कर्मचारी प्रबंधन की रणनीति के तौर पर किया जाता है। यह एक व्यक्ति में प्रतिस्पर्द्धा और पहचान की चाहत के अहसास को अपील करती है। मसलन, उबर के ड्राइवर 'असाधारण सेवा' और 'बेहतरीन संवाद' जैसे तमगे हासिल कर सकते हैं।

यह सच है कि गेमिफिकेशन बाकी किसी भी अन्य रणनीति के मुकाबले कहीं अधिक रोमांचित करती है। लेकिन यह सुविचारित एवं व्यवस्थित तरीके से डिजाइन होना चाहिए अन्यथा 'कोबरा इफेक्ट' हो सकता है। ब्रिटिश काल में दिल्ली में कोबरा सांपों की संख्या बढ़ने से चिंतित सरकार ने हरेक मृत कोबरा लाने पर इनाम देने का ऐलान किया था। शुरू में यह तरकीब कारगर होती दिखी लेकिन इसके चलते बड़ी संख्या में सांप मारे जाने लगे। हालत यह हो गई कि अतिरिक्त कमाई के लिए लोगों ने कोबरा पालना शुरू कर दिया था।

संगठनों को व्यवस्था इस तरह लागू करनी चाहिए कि अनचाहे एवं अवांछनीय तरीके से भी किसी गेमिफिकेशन पहल के दुष्प्रभाव न सामने आएं।

कानाफूसी

चुनाव चिह्न

सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की कि वह उसके चुनाव चिह्न यानी मक्के और हंसिए के चित्र की गुणवत्ता में सुधार करे। पार्टी ने दावा किया कि अब तक सन 1952 में हाथ से बनाए गए एक चित्र का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने पत्र में कहा कि भाकपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के बाद से अब तक सारे चुनाव एक ही चुनाव चिह्न पर लड़े हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को मुद्रण की नई तकनीक अपनानी चाहिए और चुनाव चिह्न रंगीन मुद्रित हो ताकि वे बेहतर नजर आएं और उनको पहचानना आसान हो। ऐसा करने से चुनाव चिह्न को लेकर प्रत्याशियों की ओर से आ रही शिकायत दूर होगी। उन्होंने कहा कि भाकपा कमजोर और श्रमिक वर्ग के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है इसलिए उसका चुनाव चिह्न ऐसा होना चाहिए कि आसानी से पहचाना जाए।

हवा का रुख

कई लोग यह मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सुखराम का राजनीतिक परिवार इस बात का संकेतक है कि राज्य में राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है। सोमवार को सुखराम ने अपने पोते आश्रय शर्मा के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा ने वर्ष 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के कुछ सप्ताह पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। उन चुनावों में कांग्रेस को पराजय हाथ लगी थी और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो सुखराम के पोते को मंडी लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। सुखराम वर्ष 1996 में दूरसंचार घोटाले से चर्चा में आए थे। उसके बाद उन्हें और उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया गया था। ऐसे संकेत हैं कि सुखराम के बेटे अनिल शर्मा भी जल्दी भाजपा छोड़ सकते हैं।

आपका पक्ष

चिनूक हेलीकॉप्टरों से सेना को मिलेगा बल

भारतीय वायुसेना में पिछले दिनों अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक को शामिल किया गया। यह अधिक वजन उठाने में सक्षम है। इससे वायुसेना को अधिक बल मिल सकेगा। दो इंजन और टैंडेम रोटर वाले चिनूक हेलीकॉप्टर दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी सैन्य अभियान चला सकते हैं। इसकी मदद से जवानों, विस्फोटक सामग्री हथियार और ईंधन ले जाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से भारी सैन्य वाहनों को भी नियत स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर दुर्गम ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी सामान ले जाने में सक्षम है। इससे वायुसेना को सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम स्थलों तक सैन्य सामान पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा देश में आपदा के समय भी इस हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाई जा सकती है। बारिश के मौसम में किसी क्षेत्र में बाढ़ आने से लोगों को बचाने में यह हेलीकॉप्टर मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना में चार चिनूक हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

सोमवार को चार चिनूक हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया गया *-पीटीआई*

अंतरजातीय विवाहों को मिले प्रोत्साहन

देश की उन्नति के लिए लोगों के बीच सौहार्द तथा एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का होना बेहद आवश्यक है। एक ऐसा समाज जहां भेदभाव का स्थान न हो वह सही मायने में मानव कल्याण के प्रति सजग समाज कहलाने का पात्र होता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि सरकारी प्रयासों से विभिन्न कानूनी प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की सामाजिक स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। लेकिन यह बदलाव शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र अभी इससे अछूते हैं। अधिकांश ग्रामीण एवं शहर की कुछ आबादी आज भी पुरानी मानसिकता को ढो रही है। इसे जड़ से समाप्त करने का एक बेहतर जरिया अंतरजातीय विवाह है। सामाजिक एकीकरण के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत समाज सुधारकों द्वारा आजादी के पहले ही रेखांकित किया गया था। आज भी शिक्षित युवा अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। लेकिन यह केवल प्रेम विवाह तक ही सीमित है। इसके आंकड़े भी बेहद कम हैं। केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों ने समय-समय पर अपने स्तर पर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की योजनाएं चलाई हैं। लेकिन समाज में जाति से बाहर दूसरी जाति में शादी को लेकर भय इस तरह हावी है कि इस योजना का लाभ कुछ लोग ही उठा पा रहे हैं। इसका कारण अंतरजातीय विवाह को लेकर सरकार की निष्क्रियता या एक सुरक्षात्मक माहौल प्रदान न कर पाना भी हो सकता है। समाज के प्रबुद्धजनों एवं नई पीढ़ी के युवाओं को आगे लाना होगा। ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना होगा जिसमें अलग-अलग जाति के बीच विवाह संपन्न होने लगे। सामाजिक समरसता के लिए जाति बंधन को तोड़ना बेहद जरूरी है जिससे जात-पात की हिंसा को रोका जा सके।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।